ग्रह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना जो पहले स्वतंत्रता सैनिक पेंशन योजना के नाम से ज्ञात थी में 1880 से 300/–रुपये प्रतिमास की दर से पेंशन की व्यवस्था है। बढ़ी हुई पेंशन देने के लिए कोई सामान्य निर्णय नहीं किया गया है। किन्तु सामान्य राशि से अधिक पेंशन अन्य बातों के साथ-साथ आवेदक की यातनाओं, वृद्ध-अवस्था, परिवार के दायित्वों और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार के स्वनिर्णय से बहुत कम और किसी मामले में स्वीकृत की जाती है। मासिक पेंशन की राशि प्रत्येक अवस्था में उसके गुणदोष के आधार पर निश्चित की जाती है और अब तक स्वीकृत की गई उच्चतम राशि 500–रु० प्रतिमास है। स्वतंत्रता सैनिक पेंशन योजना के शुरु होने के गत 10 वर्षों के दौरान बढ़ी हुई पेंशन अब तक योजना के अन्तर्गत 123861 लाभ प्राप्तकर्ताओं में से 38 व्यक्तियों से अधिक को स्वीकृत नहीं की गई है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से आतंकवादियों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक

603. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किए जाने के बाद आतंकवादियों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगी है

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधिनियमित होने से राज्य सरकार को आतंकवादी और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कारगर कार्यवाई करने में मदद मिलेगी।

लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना

604. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1.15 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया और निर्णय के बाद राजस्थान के किन-किन जिलों में खासतौर से पाली जिले में कितने व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया है, उन्हें क्या रोजगार सुलभ कराया गया है और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ख) उन मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए हैं, जिनका पेशा लगभग समाप्त हो गया है और पाली जिले में जिनकी संख्या 10,000 है तथा क्या उन्हें रोजगार देने हेतु कोई योजना बनाई गई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) छठी पंचवर्षीय योजना में 10.17 करोड़ लोगों को गरीबी के स्तर से ऊपर उठाने का प्रयत्न किया गया है। इसका वार्षिक औसत लगभग 2.03 करोड़ होता है, 1.15 करोड़ नहीं। राज्यवार और जिलेवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं!

(ख) जिलेवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

Problems of the Coir Industry of Kerala

605. SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the problems faced by the Coir Industry of Kerala;